'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

प्रकाशन तिथि–15 मार्च, 2013

DL(ND)-11/6144/2013-14-15

R.N.I. No. 68180/98

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 8 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 मार्च, 2013

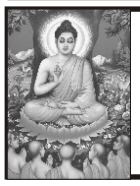

मादक पदार्थों से दूर रहें।

-गौतम बुद्ध

कम्युनिस्टों की जातीय सोच

डॉ. उदित राज

आशीष नंदी ने जयपुर साहित्य सम्मेलन में जो कहा पूरा असत्य नहीं है, उसका एक हिस्सा सच्चाई से भरा हुआ है। उन्होंने कहा था कि दलित–पिछड़े भ्रष्ट हैं और अब जनजाति के लोग भी हो रहे हैं। यह भी कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार कम है, लेकिन 100 वर्ष में कोई दलित और पिछड़ा नेतृत्व नहीं पैदा हुआ। इसका बहुत गहरा अर्थ है कि आखिर क्यों नहीं कम्युनिस्टों के गढ़ में कोई दलित एवं पिछड़ा नेतृत्व उभरा जबकि वहीं सबसे ज्यादा होना चाहिए था। पूरा दलित–आदिवासी समाज सर्वहारा है। देखा जाए तो जो परिभाषा सर्वहारा की काल मार्क्स ने की थी, उससे भी कहीं ज्यादा सटीक इन पर लागू होती है, क्योंकि इनका न केवल आर्थिक शोषण हुआ, बल्कि मानसिक भी हुआ। एक तरफ कम्युनिस्ट जात–पात भी नहीं मानते तो दूसरी तरफ नेतृत्व सवर्णों के हाथ में ही क्यों है। कार्ल मार्क्स के दर्शन के अनुसार नेतृत्व सबसे पहले दलितों के पास होना चाहिए, उसके बाद जनजाति और फिर पिछड़ों के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

कार्ल मार्क्स के दर्शन ने सबसे ज्यादा बल आर्थिक शोषण पर दिया। उनका कहना था कि मजदूर उत्पादन में जितना अपना श्रम लगाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा मालिक लूट लेता है और इस लूट को उन्होंने अधिशेष मूल्य (सरप्लस वैल्यू) कहा। कार्ल मार्क्स ने जितनी ईमानदारी और पैनी दृष्टि यूरोप एवं रूस के समाज को समझने और देखने में लगायी उतना यहां पर किसी ने भी नहीं सिवाय कि 20वीं सदी में चंद लोग और उसमें डॉ0 अम्बेडकर प्रथम स्थान रखते हैं। हमारे यहां का बुद्धिजीवी वर्ग समाज परिवर्तन करने में असफल रहा और वह जाति की घेराबंदी से ऊपर उठ नहीं सका। दुर्भाग्य है कि शायद ही कोई बुद्धिजीवी इस कड़वे सच को स्वीकार करेगा कि वह सोच और लेखन में ईमानदार है और जातीय भावना से परे है। आश्चर्य होता है कि लोग यहां बोलते कुछ हैं और करते कुछ। शायद ही कोई ऐसा होगा जो जाति–व्यवस्था के खिलाफ बोलता न होगा लेकिन इसके विपरीत शायद ही कोई ऐसा होगा, जो इसको ईमानदारी से तोड़ना चाहता हो। यही मूल अंतर हमारे समाज का दूसरों से है। दूसरा समाज इतना पाखंडी, मानसिक रूप से बेईमान और दोहरा चरित्र वाला नहीं होगा।

यूरोप एवं अमेरिका में जो सर्वहारा का शोषण आर्थिक आधार पर हुआ, उससे कई गुना यहां के दलितों का सामाजिक आधार पर हुआ, लेकिन क्या कम्युनिस्ट इसको समझ सके? स्वीकार कर सके? वहां के मालिकों में कम से कम यह तो ईमानदारी रही कि उन्होंने खुद प्रयास करके समाज को हर क्षेत्र में पनपा कर, फसल काटा लेकिन जातिवादी समाज में ऐसा हुआ ही नहीं। वहां के अमीरों के ही प्रयास से शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की हुई। उन्होंने खुद तमाम तरह के उपकरणों, मशीनों एवं कलपुर्जों के इजात में न केवल लागत लगायी बल्कि स्वयं शामिल भी हुए। अभी भी शोध और विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा निवेश वे करते हैं, हालांकि परिस्थितियां बदल गयी हैं, इतनी जरूरत भी नहीं है। इस वर्ष अमेरिका ने लगभग 350 बिलियन डॉलर शोध और विकास में लगाया जो दुनिया में किसी देश से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र भी भारी धन इस पर खर्च करता है। वहां ज्यादातर अनुसंधान और विकास निजी क्षेत्र के ही द्वारा किया गया। इसका निष्कर्ष यह है कि वहां के मालिकों ने यदि मजदूरों का शोष ण किया तो कुछ देकर। साहित्य से लेकर तमाम अन्य क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिया। भले ही अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए या जीवन के आराम एवं इस्तेमाल की वस्तुओं के लिए किया हो। क्या भारतीय कम्युनिस्ट इस सच्चाई को जान सके? अगर जानते और समझते तो इनका नजरिया भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में जो शोषण हो रहा है, उससे लड़ने के लिए यहां के दलितों और पिछड़ों को नेतृत्व देते।

न केवल धर्मशास्त्रों के अनुसार बल्कि व्यवहार में भी यहां के सवर्णों ने उत्पादन के साधन में कोई खास योगदान नहीं दिया। किसी भी प्रकार के श्रम को करने में ये अपना अपमान समझते थे और आज भी कुछ है। सैकड़ों–हजारों एकड़ जमीन के मालिक होते हुए भी कभी न फावड़ा चलाते थे और न ही हल, क्योंकि इसको अपना अपमान समझते थे। इस तरह से भारतीय समाज का सवर्ण यूरोप और अमेरिका के समाज के अमीरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा परजीवी रहा है। उत्पादन के साधन के मालिक तो ये थे लेकिन अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं तो धन–सम्पत्ति भी एक सीमा तक ही पैदा हो सकी। बहुत दिन बीते नहीं हैं, मैंने अपने बचपन में गांव में देखा कि सवर्ण जमींदार भले ही भारी हानि हो जाए फिर भी थोड़ा भी देखभाल एवं श्रम से बचते थे क्योंकि यह करना उनका अपमान है। नहर में पानी ज्यादा आने से अगर फसल खराब हो रही है तो पानी रोकने के लिए भी प्रयास नहीं करते थे, क्योंकि इससे उनकी शान में कमी आती थी। खेत सूख रहा है और नहर में पानी है, तो इंतजार मजदूर का होता था कि वह आए तब सिंचाई हो, भले ही फसल सूख जाए। इस उदाहरण से सवर्णों की मानसिकता समझ में आ जाती है और जब 20वीं शताब्दी में ऐसा हुआ तो अतीत में क्या न हुआ होगा, समझना मुश्किल नहीं है।

दलितों और पिछड़ों का न केवल आर्थिक शोषण हुआ बल्कि उससे ज्यादा कहीं मानसिक। यूरोप में यदि श्रम की लूट हुई तो यहां पर श्रम और सम्मान दोनो की। भारतीय कम्युनिस्ट इनके सम्मान की लूट को कभी महत्त्व ही नहीं दिये। यही कहते रहे कि शिक्षा और शहरीकरण जैसे–जैसे बढ़ेगी जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़ों को कुछ हद तक तो कम्युनिस्ट समझाने में सफल रहे, जिससे उनका विस्तार बंगाल में हुआ। बिहार और उ0प्र0 में भी अच्छा पांव पसार रहे थे कि तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के बदलाव के झटके ने उनको और सिमटा दिया। सन् 1990 के दशक में जब रूस टूटा तो उसका असर दुनिया के कम्युनिस्टों पर पड़ा और लगातार कमजोर पड़ते गये। समयान्तराल एवं ज्ञान व विज्ञान के फैलाव के कारण सन् 1970–80 के दशक में दलित–पिछड़े अपनी भागीदारी के लिए जाग उठे। जैसे–जैसे समय बीता राजनीति के क्षेत्र में जातीय ध्रुवीकरण बढ़ता गया। आर्थिक शोषण से ज्यादा पीड़ा मानसिक थी और आज है भी, दलित–पिछड़ों के नेताओं ने समझा और इसी आधार पर इनके पीछे जातियां जुड़ गयीं। यदि इस सामाजिक और धार्मिक सच्चाई को यहां के कम्युनिस्ट मानते तो दलित और पिछड़ी जातियों के नाम से नेतृत्व न खड़ा होता बल्कि कमेरा वर्ग की पहचान से।

जब कम्युनिस्ट इस सामाजिक और धार्मिक सच्चाई को समझ सके ही नहीं तो कहां से दलित और पिछड़े नेतृत्व को उभरने का मौका देते? बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी यदि इनका नेतृत्व नहीं उभर पाया तो इसी सोची–समझी साजिश या भूल के कारण। यहां पर आशीष नंदी का बयान संदर्भित है और सही भी। कार्ल मार्क्स जैसा व्यक्ति यदि भारत में पैदा होता तो वह डॉ0 बी. आर. अम्बेडकर जैसा व्यक्तित्व का होता। यहां जातीय शोषण इस सीमा तक है कि ये दलित एवं पिछड़े मानसिक रूप से विकलांग बना दिये गये और पूर्ण रूप से भाग्यवादी। डंडे की जरूरत भी नहीं पड़ी इनको दबाने और कुचलने में, क्योंकि यह सबकुछ ईश्वरीय सत्ता का खेल माना गया। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा तो यहां के कम्युनिस्टों को हिन्दू धर्म को क्या कहना चाहिए था? वस्तुगत् स्थिति के अनुसार अफीम से भी कहीं ज्यादा खतरनाक एवं जहरीला रूप से प्रस्तुत किया जाता तब जाकर ये मानसिक शोषण से निजात पाते और मार्क्सवाद रूस के बाद भारत में जड़ जमाता। यूरोपीय देशों से भी कहीं ज्यादा उर्वरा भूमि साम्यवाद के लिए भारत थी। लेकिन यहां के सवर्ण कम्युनिस्टों ने समझा ही नहीं। एकतरफ आर्थिक शोषण की मुक्ति की लड़ाई लड़ते रहे लेकिन दूसरी तरफ बड़ा शोषण, जो मानसिक एवं सामाजिक था, उस पर आंख मूंदे रहे और इसका परिणाम अब इनको मिल रहा है।

तस्वीर बदल सकते हैं देश के कुबेर

सुनील खिलवानी

गगनचुंबी अंबानी टॉवर्स की तस्वीरों और माल्यालैंड व डीएलएफाबाद की तड़क–भड़क को देखकर झुग्गी में रहने वाले किसी गरीब बच्चे के जहन में आक्रोश नहीं पनपता, बल्कि वह इसे विस्मय से देखता है। भारतीयों ने ही डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बॉर्नरिच डॉट कॉम शुरू किया और उसे चला रहे हैं। इस वेबसाइट से आप हर श्रेणी के चुनिंदा लग्जरी उत्पादों का प्रामाणिक लग्जरी अनुभव ले सकते हैं। इनमें ऑटोमोबाइल्स, गैजेट्स और ज्वेलरी से लेकर बहुत ऊंची कीमत वाले रियल इस्टेट, संग्रहणीय वस्तुओं और नीलामी बाजार के लग्जरी ट्रेंड का विश्लेषण शामिल है। इन दिनों ऐसा कहीं और नहीं होता।

कई देशों में तो धनाढ्य वर्ग आम लोगों के निशाने पर आ चुका है। असंतुष्ट होकर लोग सड़कों पर उतर आए। अमेरिका का अक्यूपाई वाल स्ट्रीट और इटली का द इनडिगनाडोस इसका उदाहरण है। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन सहित तकरीबन पूरे यूरोप की सरकारें अमीरों पर ज्यादा कर और लेवी लगाकर अपने खजाने को भरने की कोशिशें कर रही हैं, क्योंकि वे वित्तीय संकट से जूझ रही हैं।

संपन्न लोगों की धरती अमेरिका में इस बात पर सहमति बढ़ती जा रही है कि अमीरों को लोकहित के कामों के लिए आगे आना चाहिए। वहां हालांकि यह काम उच्च कर के माध्यम से नहीं, बल्कि परोपकार के जरिये होने की उम्मीद की जा रही है। हाल के वर्षों के दौरान वहां लोकहित से जुड़े कामों के लिए धन देना, सामान्य बात होती जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि करियर के आखिरी पड़ाव पर लोग इस तरफ रुचि दिखा रहे हों, युवा उद्यमी भी इस दिशा में सक्रिय हैं।

वहीं, भारत को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक कार्यों के लिए अमीरों की तरफ से दिये जा रहे दान की स्थिति बहुत सामान्य है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, भारत के 100 सबसे धनाढ्यों की कुल संपत्ति तकरीबन 250 अरब डॉलर है। इनमें दो–तिहाई अरबपति हैं। अब अगर हम भारत के शीर्ष 10 दानदाताओं की सूची देखें, तो पाएंगे कि अजीम प्रेमजी इसमें सबसे ऊपर हैं। केवल तीन धनाढ्यों ने अपनी कमाई का दस फीसदी या उससे अधिक का दान किया है। जबकि अमेरिका का धनाढ्य वर्ग अपनी कमाई का औसतन नौ फीसदी से अधिक सालाना तौर पर दान करता है।

अमेरिकी अमीर अपनी आमदनी का 9 प्रतिशत गरीबों के उत्थान में खर्च करते हैं। जबकि भारत का सबसे अमीर अंबानी आधा प्रतिशत ही खर्च करता है, फिर भी दलित, आदिवासी, पिछड़ें और गरीब विरोध नहीं करते जबकि यूरोप और अमेरिका में जनता ने इन्हें अपने निशाने पर ले लिया है और और सवाल कर रही है कि ये व्यवस्था अन्याय और लूट पर खड़ी नहीं है। इनके पास इतना धन कहां से आया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे श्रम और कमाई की लूट है। अब इसमें भागीदारी लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का साथ देना होगा।

भारत की सूची में मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर हैं और उन्होंने अपनी कुल संपत्ति (21 अरब डॉलर) का केवल आधा फीसदी दान किया है। इस सूची में शामिल दस अमीरों ने करीब दो अरब डॉलर से कुछ अधिक रकम लोकहित के कार्यों के लिए दिया। यह भारत के उच्च धनाढ्य वर्ग की कुल संपत्ति का बहुत मामूली हिस्सा है।

सामाजिक कार्यों के लिए दान देने की प्रवृत्ति, विशेषकर बड़े स्तर पर, खुद–ब–खुद विकसित नहीं होती। निश्चित रूप से अमेरिका में निजी दानदाताओं का एक लंबा इतिहास रहा है। पर हालिया पुनरुत्थान 1990 के दशक के अंत से शुरू हुआ, जब सीएनएन के टेड टर्नर ने अचानक एक सार्वजनिक भाषण में बेहद शानदार तरीके से कहा कि सामाजिक कार्यों के लिए वह एक अरब डॉलर मुहैया करा रहे हैं।

उनके इस कदम से अमीरों, स्लेट जैसी मीडिया वेबसाइटों और निगरानी समूहों की ओर से धनाढ्यों की खोज, उनकी दान संबंधी दस्तावेज को लोगों के सामने लाने और टर्नर का अनुकरण करने के लिए अन्य लोगों को आगे बढ़ाने का दबाव बना। इसी क्रम में 2000 में बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स ने अपना फाउंडेशन शुरू किया। फिर 2006 में वारेन बफेट ने 31 अरब डॉलर की रकम गेट्स फाउंडेशन को दान कर दी और संक्रमित बीमारियों से लड़ने और शिक्षा में सुधार के लिए सहयोग का वायदा किया।

बफेट का दान केवल अपने आकार की वजह से ही परिवर्तनकारी नहीं था, बल्कि वह फैसला इसलिए भी अहम था, क्योंकि इसके तहत उन्होंने अपने नाम से नया फाउंडेशन न स्थापित करके एक ऐसी संस्था को समर्थन दिया, जो पहले से समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहा था। समाजसेवी संगठनों की समृद्ध परंपरा की तरह ही लोकहित में निजी दान का इतिहास भारत में भी पुराना है। पर मौजूदा वक्त में भारतीय पूंजीवादी दान प्रणाली का शायद ही कोई ऐसा चिह्न दिखाई पड़ता है, जो कई अहम समस्याओं– जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सुरक्षा– को सुलझाने के लिए बड़े पैमाने पर निजी दान देकर सरकार का बोझ कम कर सके। वैसे इन समस्याओं से जूझने की ऐतिहासिक जवाबदेही सरकार की रही है, लेकिन वित्तीय तंगी के चलते वे इस दिशा में दृढ़ इच्छा नहीं दिखा पा रही हैं।

अजीम प्रेमजी के अलावा भारतीय दानदाताओं की सूची में शिव नादर, नंदन और रोहिणी नीलेकणि, रतन टाटा जैसे कुछ अन्य लोग भी हैं। साथ ही कुछ उत्साहजनक संकेत भी मिल रहे हैं। पिछले वर्ष की एक रिपोर्ट में बेन ऐंड कंपनी ने बताया है कि दानदाताओं के आधार में विस्तार हो रहा है और नए युवा दानदाताओं की रुचि इस तरफ बढ़ी है। यह जरूरी है, क्योंकि निजी दानदाताओं में बड़े पैमाने पर प्रभावकारी परिवर्तन पैदा करने की क्षमता मौजूद है। यह ज्यादा समावेशी है।

उदाहरण के लिए अमेरिका में सभी संस्थाओं की 38 अरब डॉलर की तुलना में 2009 में निजी दानदाताओं ने धर्मार्थ कार्यों के लिए 227 अरब डॉलर दान दिए। इसलिए अति अमीरों को उनके धन के इस्तेमाल के प्रति ज्यादा जवाबदेह होने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ–साथ हमें मध्यम अमीरों को भी दान की प्रवृत्ति आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

(साभार–अमर उजाला)

जाति और भ्रष्टाचार पर गोष्ठी का आयोजन

यूपी। ''जाति और भ्रष्टाचार'' मुद्दे पर साहिबाबाद के वसुंधरा स्थित मेवाड़ संस्थान के विवेकानंद सभागार में 16 फरवरी को एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज शामिल हुए। इस अवसर पर डॉ. उदित राज ने कहा कि जब तक समाज से जाति की भावना नहीं जाएगी तब तक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण ही जातिगत भावनाएं है। इस आयोजन में क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, समाजसेवी एवं संस्थान तथा मेवाड़ विश्वविद्यालय के सभी सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बाबूलाल ने किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होकर गोष्ठी को सफल बनाया।

डॉ. उदित राज का स्वागत करते मेवाड़ संस्थान के चेयरमैन अशोक गाडिया।

'आरक्षण जीने-मरने का सवाल' - डॉ. उदित राज

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण अब जीवन–मरण का सवाल हो गया है। हक की लड़ाई के लिए एकजुटता की जरूरत है। इसके बिना जो कुछ मिला हुआ है वह भी चला जाएगा।

नागौरी गेट स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित सभा में मुख्य अतिथि उदित राज ने कहा कि लोग नारे लगाते हैं कि आप संघर्ष करो, हम साथ हैं, लेकिन दुःख तब होता है जब हम संघर्ष के लिए सड़क पर उतरते हैं तो बहुत कम लोगों का साथ मिल पाता है। उन्होंने आगे कहा कि देश तभी मजबूत हुआ है, जब आजादी के बाद दलित जातियों को आरक्षण मिला और उन्होंने राजनीति व सरकारी नौकरियों में अपनी जगह बनाई।

डॉ. राज ने आगे कहा कि केंद्र सहित राज्य सरकारें दलितों के पदों पर नौकरियां देने की बजाय इन कार्यों को ठेकाप्रथा के जरिए करवाकर आरक्षण खत्म करना चाहती है। अब तो सफाई कार्य भी ठेके पर कराया जा रहा है। आरक्षण खत्म हो रहा है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा। दलित वर्ग में शिक्षा बढ़ी है, लेकिन नौकरियां कम हुई। इससे पहले विभिन्न वर्गों के. भगवानराम फौजी, चतरराम देशबंधू, श्यामलाल नागौरी, चंदनमल नवल, चंद्रप्रकाश, थांवरदास खिंची, मूलचंद, बाबूलाल चांवरिया, लक्ष्मण सिंह सिंघाड़िया, बीएल भाटी ने सभा को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का दलितों के साथ वादाखिलाफी

दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय दलित महापंचायत एवं सम्मान रैली को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री चरणजीत सिंह अटवाल ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दिलाने की लड़ाई, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, हम सारे लोग अपनी–अपनी पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर, अपने मसीहा को देश में मान–सम्मान दिलाने के लिए एक सामाजिक मंच पर इस महापंचायत में बैठे हैं। समिति ने इसके पहले नागपुर महाराष्ट्र में रेल रोको आंदोलन की तैयारी की थी, मैं नागपुर भी गया था, लेकिन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने हमें चर्चा करने के लिए दिल्ली में अपने निवास पर बुलाया। समिति के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक की। उनको मांग पत्र दिया। उन्होंने हमारे मांग पत्र को पढ़कर, हमसे चर्चा करके, मांगों पर सहमति जताई। उन्होंने भरोसा दिया था कि इन मांगों पर कार्यवाही होगी। इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमिटी बना रहे हैं जो कार्यों के लिए विस्तृत रिपोर्ट देगी। प्रधानमंत्री जी के आश्वासन और अनुरोध पर नागपुर में आयोजित रेल रोको आंदोलन समिति ने स्थगित कर दिया था।

प्रधानमंत्री जी ने जो उच्चस्तरीय कमिटी बनाई, उसमें हमारे समिति के सदस्यों को नहीं रखा गया। लेकिन अब इस समिति की जो रिपोर्ट सरकार ने बनवाई है, उसमें केवल परिनिर्वाण स्थल पर भव्य स्तूप बनाने की मांग मंजूर की गई है। राजघाट जैसा कानूनी दर्जा देने और आसपास के बंगलों का अधिग्रहण करके बड़ा भूमि परिसर देने की मांग मंजूर नहीं की गई है। इन मांगों पर समिति ने विचार नहीं किया है। हमसे जो वादा सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया था, उसको उन्होंने निभाया नहीं है, यह उनकी दलितों के साथ वादाखिलाफी है। आज दलित महापंचायत में जो सात प्रस्ताव पारित हुए हैं, यह देश के प्रत्येक दलित की आवाज एवं भावना है। इस पर केंद्र सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। सरकार को चुनकर सत्ता में बिठाने में देश के दलितों की बड़ी भूमिका है। सरकार को और दलितों को दोनों को ही इस बारे में सोचना पड़ेगा।

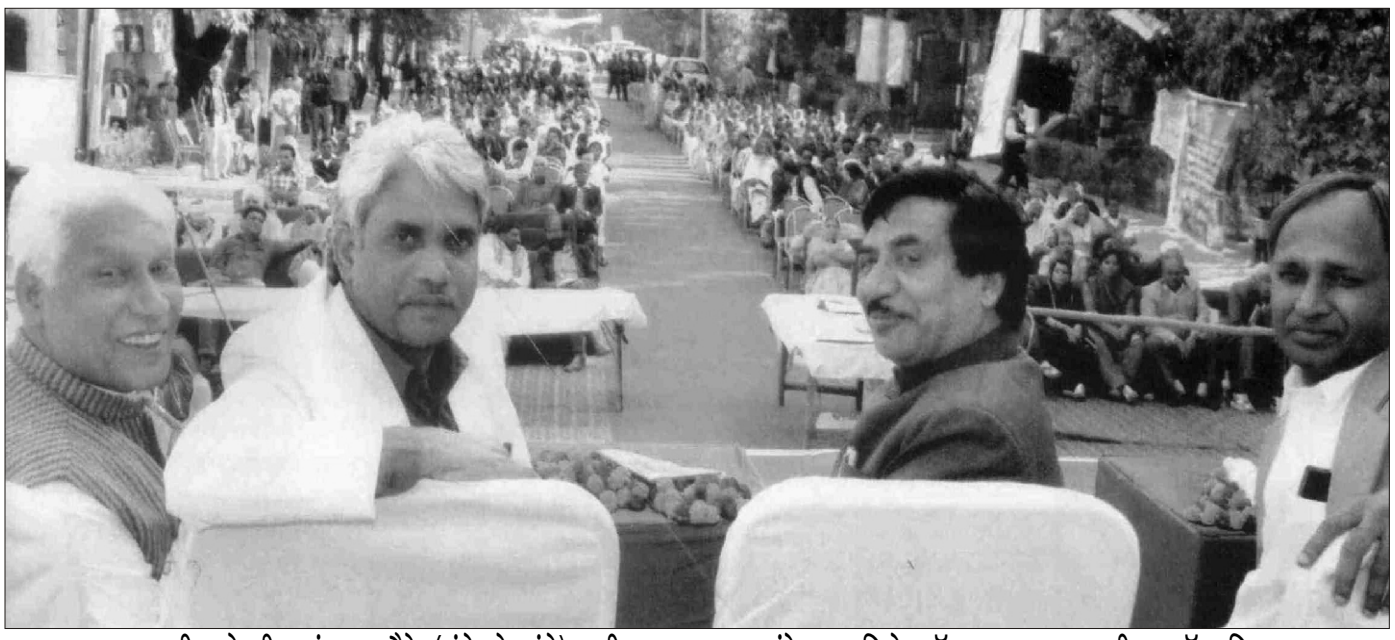

अपार भीड़ के बीच मंच पर बैठे (बांये से दांये) : टी. एम. कुमार, इंद्रेश गजभिये, डॉ. सत्यनारायण जटीया, डॉ. उदित राज।

यह उपेक्षा दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा– उदित राज

जब दिल्ली में सभी महापुरुषों की समाधि–स्मारकों को हजारों एकड़ जमीन पर बनाकर, अरबों रूपए खर्च करके सजाया, चमकाया गया है, सम्मान दिया गया है तब बाबा साहेब की परिनिर्वाण उपेक्षित क्यों है। यह केंद्र सरकार का जातिवादी बर्ताव है तो इसमें हम दलित नेताओं की भी बहुत बड़ी चूक है। हम इतने नेता दिल्ली में रहते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया, लेकिन अब हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमारे लोगों की आदत बिगड़ गई है, अब आदत सुधारना पड़ेगा। मैंने लड़–लड़कर प्रमोशन में आरक्षण के कई आदेश सरकार से निकलवाये। जब लोगों को प्रमोशन मिल गया तो वे वैष्णव देवी प्रसाद चढ़ाने और धन्यवाद करने गये। ये लोग एक मिठाई का डब्बा लेकर मेरे घर नहीं आये। यह किस तरह की ईमानदारी है भाई। असल में दलितों की लड़ाई हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लड़ रहे हैं, ये लोग किसी से डरते नहीं है। केंद्र सरकार की इस प्रकार उपेक्षा को अब देश का दलित बर्दाश्त नहीं करेगा।

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का
अखिल भारतीय परिसंघ

सूचनार्थ

केंद्र सरकार की नौकरियों में बहुजन

गत् 20 दिसंबर, 2012 को वी नारायणसामी, राज्यमंत्री, कार्मिक, जनशिकायत व पेंशन ने राज्यसभा में डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया के द्वारा किए गए एक सवाल के उत्तर में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति की केंद्र सरकार की नौकरियों में उपस्थिति के बारे में जानकारी दी थी। ओबीसी, दिनांक 01.01.2011 तक निम्नवत था :

समूह	ओबीसी संख्या	ओबीसी प्रतिशत
क	5,357	6.9
ख	13,897	7.3
ग	3,46,433	15.3
घ	81,468	17

राज्य मंत्री ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि ''केंद्र सरकार की सेवाओं में अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त किसी और माध्यम से भर्ती के मामले में ओबीसी को 25.84 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। केंद्र सरकार की सेवाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है, क्योंकि उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सितंबर, 1993 से शुरू की गई थी। इन वर्गों के जो सदस्य 1993 के पहले भर्ती हुए थे, उनकी भर्ती बतौर सामान्य उम्मीदवार की गई थी। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान 1955 से उपलब्ध है।'' **(साभार : फारवर्ड प्रेस)**

एससी, एसटी व ओबीसी का प्रतिनिधित्व दिनांक 01.01.2011 तक निम्नानुसार था :

समूह 'क'

	प्रतिशत में	संख्या में
एससी	11.5	8,922
एसटी	4.8	3,732
ओबीसी	6.9	5,357

समूह 'ख'

	प्रतिशत में	संख्या में
एससी	14.9	28,403
एसटी	6	11,357
ओबीसी	7.3	13,897

समूह 'ग'

	प्रतिशत में	संख्या में
एससी	16.4	3,70,557
एसटी	7.7	1,74,562
ओबीसी	15.3	3,46,433

समूह 'घ'

	प्रतिशत में	संख्या में
एससी	23	1,10,515
एसटी	6.8	32,791
ओबीसी	17	81,468

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

हम मुसलमानों को अपनी रणनीति बदलनी होगी।

डॉ. सैयद जफर महमूद

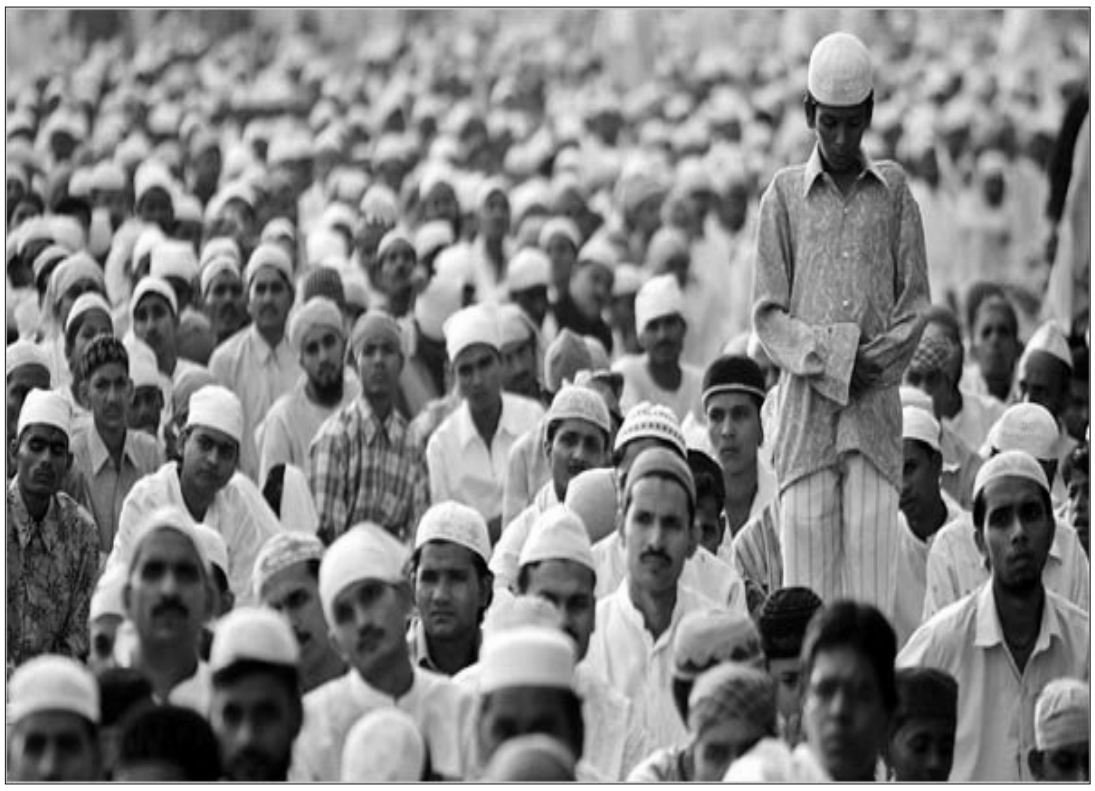

कुरान पाक में सूरह बनी इस्राईल की आयत 70 में अल्लाह तआला का यह फ़रमान हैं कि हम ने आदम की औलाद यानि इंसानों को सम्मान और मर्यादा दी है। सूरह अलहुजरात में कहा गया कि इंसानों के विभिन्न कुटुम्ब और क़बीले बनाए गए हैं जिससे वह आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं। इस तरह एक तरफ़ अल्लाह ने हम इंसानों को व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का सम्मान करने और मूल्य पहचानने का आदेश दिया और दूसरी तरफ़ वर्गीय तथा सामुदायिक स्तर पर समानता, सम्मानता तथा सहयोग का सम्बंध बनाने की सीख दी। इनके अतिरिक्त अन्य कई सूरतों की बहुत सी आयतों से यह पता चलता है कि कामयाब व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन के लिए अल्लाह के दिशा–निर्देश विभिन्न सार्थक निहितार्थ रखते हैं। इस संबंध में अल्लाह ने अपने दिशा–निर्देश केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रखे हैं बल्कि उनका महत्तव सारी मानवजाति और समस्त वर्गों के लिए है।

1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक का इतिहास यह दर्शाता है कि देश के मुसलमान अन्य सभी समुदायों की अपेक्षा सामाजिक, शैक्षिक एंव आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ कर रह गए हैं। सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन की रिपोर्टों के बाद यह सच्चाई अब ढकी–छुपी नहीं रह गयी है। यह भी साफ़ हो गया है कि इस पिछड़ेपन का मुख्य कारण वह नीतियां है जो मुसलमानों के सम्बंध में बनाई जाती रहीं हैं। जैसेः (1) अनुसूचित जातियों के संबंध में 1950 में जारी किए गए आदेश में प्रशासन की साज़िश से मुसलमानों को अलग–थलग करके उनके दलित वर्गों को संसद, विधान सभाओं, प्रशासनिक सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं के 15 प्रतिशत भाग से वंचित कर दिया जाना, (2) मुसलमानों की बहुलता वाले चुनाव क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया जाना इसके बावजूद कि वहां अनुसूचित जातियों की आबादी ज्यादा नहीं, (3) मुसलमानों के साथ हर क्षेत्र में भेदभाव बरतना, और (4) कुछ मुसलमानों को केवल दिखावे के लिए शासन के कुछ पदों पर आसीन कर देना, आदि।

पिछले 65 सालों से मुसलमानों को उनके अस्तित्व के मुद्दों में नकारात्मक रूप से उलझाए रखा गया है। मुसलमानों का वोट उनकी सुरक्षा की गारंटी के आधार पर मांगा जाता है। दूसरी तरफ़ ग़ैर–मुस्लिमों से यह कहा जाता है कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। मुसलमान को विदेशी या आतंकी घोषित कर देना तो बाएं हाथ का खेल है। मुस्लिम नौजवानों को निराधार आरोपों पर वर्षों तक जेल में रखना और अदालत में आरोप सिद्ध न होने पर चुपके से छोड़ देना देश की राजनीतिक और प्रशासनिक संस्कृति बन गयी है। पाठ्यपुस्तकों में परोक्ष रूप से मुसलमानों को नीचा दिखाना राष्ट्रीय पाठयक्रम की नीति बना ली गयी है। ग़ैर–मुस्लिम बहुसंख्यक वर्ग की पीढ़ियां इसी राष्ट्रीय स्वभाव के साथ पल कर जवान हो रही हैं। इन योजनाबद्ध नीतियों से मुसलमानों की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया जा रहा है। जिसकी वजह से मुसलमान हमेशा अपने बचाव में लगे रहते हैं। ऐसे में वे अपनी तरक्क़ी और उन्नति की तरफ़ कैसे ध्यान दे सकते हैं। इस साज़िश के चलते ही कुछ शक्तियां भारतीय राजनीति के कबड्डी मैदान में मुसलमानों के पाले में घुस कर उन को सुरक्षात्मक खेल खेलने पर मजबूर करने में सफ़लतापूर्वक लगी हुई हैं।

इक्कीसवीं सदी के इस प्रारंभिक चरण में हम भारतीय मुसलमानों पर अपनी बेहतरी के लिए बहुत कुछ करने की भारी ज़िम्मेदारी है। हमें इस मुस्लिम विरोधी राष्ट्रीय धारा को बदलने के लिए सोच समझ कर प्रभावी उपाय करने होंगे। 1950 का प्रशासनिक आदेश जारी होने के पीछे सरकारी फ़ाइलों में की गयी कार्रवाई का विवरण सूचना के अधिकार क़ानून के अन्तर्गत सरकार 2013 में भी देने को तैयार नहीं है। मुसलमानों की बहुलता वाले चुनाव क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। आई.पी.एस. की 1400 अतिरिक्त भर्तियों के लिए उस सीमित चयन प्रक्रिया से भी सरकार हटने को राज़ी नहीं है जिससे मुसलमानों को सीधा नुक़सान पहुंचाया जा रहा है।

हम मुसलमानों को देश की चुनावी राजनीति में पिछलग्गू बने रहते हुए 65 साल हो गए। इस तरह तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम बुरी तरह फ़ेल हैं और अपमानित हो रहे हैं। अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक जीवन से खिलवाड़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। समय आ गया है रणनीति बदलने का। हमें अब फ़ौज में पैदल पिछलग्गू के बजाए इण्डा बरदार बनना होगा।

1950 में हमारे संविधान ने देश की आबादी के 20 प्रतिशत दलितों को और फिर 42 प्रतिशत पिछड़ों को आरक्षण दिया। इस से गिरे–पड़े लोगों को ऊपर उठने का अवसर मिला। किन्तु इससे उनका केवल शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर ही ऊंचा हुआ पर उनकी सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव या बेहतरी नहीं आई। सामाजिक स्तर पर उनकी स्थिति पहले ही जैसी है। यही वजह है कि वे आज भी हीनता एंव वंचिता से पीड़ित हैं। ग़ैर–अनुसूचित जातियों तथा ग़ैर–पिछड़े वर्गों की धारणा तथा चेतना में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक स्तर के प्रति कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि इसके लिए करोड़ों लोगों को हज़ारों साल पुरानी संस्कृति से पिण्ड छुड़ाना पड़ेगा जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। इस उद्देश्य से देशवासियों के मस्तिष्क में बदलाव लाने के लिए 1950 का संवैधानिक ढांचा तथा उसके संशोधन व सुधार भी कुछ काम नहीं आए। इसके लिए हमारा संविधान कैलाएडोस्कोप (Kaleidoscope) (यानि ऐसा खिलौना जिसे घुमाकर देखने से उसमें विभिन्न रंगों के विभिन्न धारा दिखाई देते हैं) न बन सका।

हम मुसलमानों को अच्छा मुसलमान बनना होगा। हम आपस में भी समानता की इस्लामी शिक्षाओं को व्यवहार में लाएं और साथ ही देशवासियों में पिछड़े वर्गों की तरफ़ मुहब्बत का हाथ बढ़ाएं। इस तरह वे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। फिर हम दोनों की संयुक्त राजनीतिक शक्ति (जनगणना आंकड़ों पर निर्भर करते हुए भी) 35.9 प्रतिशत तक जा सकती है। इस लिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके साथ मिलकर संयुक्त प्रयास करना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के मानस में इस पीड़ादायक खालीपन को भरने के लिए, इस पर मरहम लगाने के लिए और उनकी भावनाओं को राहत देने के लिए मानवता के नायक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैह वसल्लम ने 1400 साल पहले हर इंसान की व्यक्तिगत आज़ादी और समानता के अधिकार का ऐलान कर दिया था। तो उस पैग़म्बर के उम्मती होने के नाते हम क्यों न इस देशवासियों में मानसिक बदलाव की जिद्दोजहद करें। इसके लिए हम क्यों न उस पैग़म्बराना संदेश और शिक्षा का प्रचार करें। और अल्लामा इक़बाल की इस भविष्यवाणी को सच कर दिखाएः

''निकल के सहरा से जिस ने रोमा की सल्तनत को पलट दिया था,
सुना है यह कुदसियों से मैंने वह शेर फिर होशियार होगा।''

हमें इस्लाम के बुनियादी संदेश को समझना होगा और उस पर अमल करना होगा। मैंने इस अहम मुद्दे पर दलित नेता उदित राज जी से लम्बी वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि वह जस्टिस मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट से सहमत हैं कि 1950 के अध्यादेश में से पैराग्राफ़ 3 को निकाल दिया जाए और इस तरह अनुसूचित जाति की परिभाषा से धर्म की शर्त हटा दी जाए। उन्होंने अपना यह वचन लिखित रूप से दे दिया है। तो क्यों न हम अपने पैग़म्बराना संदेश के साथ आगे बढें और मुस्लिम विरोधी दानव को सींगो से पकड़ कर क़ाबू में कर लें। इस संबंध में ईसाई धर्म गुरुओं से भी बातचीत हुई है। वह भी 65 साल से चली आ रही इस महरूमी से बहुत व्याकुल हैं और इस अभियान में हर तरह से साथ देने को तैयार हैं। अगर 1950 के अध्यादेश से पैरा 3 को निकाल दिया जाए तो मुसलमान नाई, मुसलमान लोहार, मुसलमान मोची आदि को भी वही सुविधाएं मिलने लगेंगी जो ग़ैर मुस्लिम नाई, ग़ैर मुस्लिम लोहार और ग़ैर मुस्लिम मोची आदि को पिछले 65 साल से मिलती आ रही हैं। यानि संसद, विधान सभाओं, ज़िला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों में वह आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के हक़दार होंगे, हर साल यू.पी.एस.सी के सिविल सर्विस परीक्षा के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती में आरक्षित पदों के लिए हक़दार होंगे।

इसके लिए हम मुसलमानों को अच्छा मुसलमान बनना होगा। हम आपस में भी समानता की इस्लामी शिक्षाओं को व्यवहार में लाएं और साथ ही देशवासियों में पिछड़े वर्गों की तरफ़ मुहब्बत का हाथ बढ़ाएं। इस तरह वे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। फिर हम दोनों की संयुक्त राजनीतिक शक्ति (जनगणना आंकड़ों पर निर्भर करते हुए भी) 35.9 प्रतिशत तक जा सकती है। इस लिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके साथ मिलकर संयुक्त प्रयास करना चाहिए।

दो दिवसीय छात्र नेतृत्व विकास शिविर संपन्न

हर्षवर्धन दवणे

नांदेड (महाराष्ट्र) में दलित आदिवासी और पिछड़े छात्रों का नेतृत्व विकास शिविर अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय डॉ. उदित राज के मार्गदर्शन में 09 और 10 मार्च को संपन्न हुआ। इस नेतृत्व विकास शिविर को डॉ. उदित राज ने मार्गदर्शन करत हुये कहा की, भूमंडलीकरण के दौर में जाति का अस्तित्व बढ रहा है। सरकारी नौकरी में हमें नौकरियां थी, इसके वजह से दलित आदिवासियों का थोडा विकास हुआ मगर वर्तमान स्थिति में सरकारी नौकरियां ही नहीं रही। इस तरह से हम गुलामी की ओर दुबारा जा रहे हैं। इससे अगर बचना है तो छात्र और युवा आगे आके निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करे। निजी क्षेत्र का आंदोलन युवा और छात्र के बिना संभव नहीं है। छात्र और युवकों के अपने और आने वाले अपने नस्ल के अस्तित्व को बचाने के लिए ये आंदोलन जरुरी है। हमारी समस्याएं सवर्ण छात्र के संगठन समझ नहीं सकते, ये जानकर भी हम अनजान बन रहे हैं। इसलिए हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़े छात्र और युवाओं का राष्ट्रीय संगठन अब जरुरी है और ये शिविर इसके लिए पूर्व तैयारी है।

इस शिविर में डॉ. इंदिरा अठावले ने छात्र संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में छात्रों का मार्गदर्शन किया। इसी बीच डॉ. राजेंद्र गोणारकर ने भारत के विविध विचार प्रणाली और आंबेडकरवाद विषय और प्रोफेसर सचिन नरंगलेजी ने सोशल नेटवर्किंग के बारे में लोगों को बताया।

इस शिविर के निष्कर्ष सत्र मे 60 छात्रों ने एक महीने के अंदर छह हजार छात्रों एवं युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी ली तो वहीं दस छात्रों ने संघटन के लिए अपना पूरा समय एक साल देने को तैयार हुए। एक साल तक पूरा समय देने वाले छात्रों के नाम : नितिन गायकवाड (नांदेड), माधव पंडित (हिंगोली), भूषण गवळी (अमरावती), गणेश वाघमारे (सातारा), बालाजी कोंडामंगल (नांदेड), स्वप्नील मुळे (हिंगोली), पंकज धाबे (परभणी), राहुल सोनाळे (नांदेड), रवि सूर्यवंशी (किनवट) हैं।

अंत मे छात्र नेता हर्षवर्धन दवणे ने कहा कि आंदोलन के बिना हमारी भागीदारी देश मे निश्चित नहीं हो पायेंगी। निजी क्षेत्र में आरक्षण से ही छात्रों और युवकों की भागीदारी निश्चित हो पायेगी। आज से हमें इस आंदोलन में लाखों की भीड़ जुटाने हेतु तैयारी करना चाहिए। चाहे भला हो या बुरा। हम निजी क्षेत्र में आरक्षण लेके रहेंगे, यह दृढ़ निश्चय शिविर में शामिल छात्रों ने हर्षवर्धन के साथ लिया।

इस शिविर को सफल बनाने के लिए नीतीन गायकवाड, बालाजी कोंडामंगल, राहूल सोनाळे, रवि सूर्यवंशी, रवि वाघमारे ने अपना अमूल्य योगदान दिया।

20 अप्रैल को झूलेलाल मैदान, नजदीक-लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में
विशाल रैली

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, पारख महासंघ व अन्य के नेतृत्व में पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए 20 अप्रैल, 2013 को प्रातः 10 बजे झूलेलाल मैदान, नजदीक-लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली को मुख्य रूप से डॉ0 उदित राज जी सम्बोधित करेगें। आप सभी से निवेदन है अपने अधिकारों को सुरक्षित कराने एवं समतामूलक भारत के निर्माण हेतु साथियों सहित पहुंचकर रैली को सफल बनाएं।

कौशल किशोर
पूर्व श्रममंत्री,
रा. अध्यक्ष, पा. महासंघ
9415005536

पी.सी. कुरील
राष्ट्रीय संयोजक,
रा. भागीदारी आन्दोलन
9415024510

भवन नाथ पासवान
प्रदेश अध्यक्ष
अजा/जजा परिसंघ
9415158866

For Your Information

Bahujans in Central Govt. Jobs

In December 2012, V. Narayanasamy, Minister of State, Personnel, Public Grievances and Pension, in reply to a question by Dr. Gyan Prakash Pilania in the Rajya Sabha, had given information about the representation of OBCs, SCs and STc in central government jobs. He said that the group-wise representation of Other Backward Classes (OBCs) in central government services as on 1 January, 2011 was as under:

Groups	Number of OBCs	Percentage of OBCs
A	5,357	6.9
B	13,897	7.3
C	3,46,433	15.3
D	81,468	17

The minister of state told the Rajya Sabha in a written answer that reservation to Other Backward Classes (OBCs) in central government services is provided at the rate of 27% in case of direct recruitment on an all India basis by open competition. In case of direct recruitment on an all India basis, other than by open competition, reservation for OBCs is provided at the rate of 25.84 %. Representation of OBCs is still low for the reason that reservation for them started only in September 1993.The representation of SCs, STs & OBCs in posts and Services of the central govt. as on 1 January, 2011 was as under :

Group 'A'

	In Percentage	In Numbers
SC's	11.5	8,922
ST's	4.8	3,732
OBC's	6.9	5,357

Group 'B'

	In Percentage	In Numbers
SC's	14.9	28,403
ST's	6	11,357
OBC's	7.3	13,897

Group 'C'

	In Percentage	In Numbers
SC's	16.4	3,70,557
ST's	7.7	1,74,562
OBC's	15.3	3,46,433

Group 'D'

	In Percentage	In Numbers
SC's	23	1,10,515
ST's	6.8	32,791
OBC's	17	81,468

(Courtesy : Forward Press)

आगामी 25 मार्च को जम्मू विधान सभा का घेराव

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, प्रदेश इकाई, जम्मू के नेतृत्व में एससी/एसटी, ओबीसी तबकों के बेहतरी की मांगों को लेकर 25 मार्च, 2013 को विधान सभा का घेराव किया जाएगा। जम्मू के प्रेस क्लब पर हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर जम्मू विधानसभा की ओर कूच करें। अंत में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

हमारी मुख्य मांगे– 1. नौकरियों, पदोन्नति में आरक्षण को पूरा का पूरा लागू करना, 2. एससी/एसटी प्लान को लागू करना, 3. मंडल कमीशन का 2 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक लागू करना, 4. शेड्यूल्ड ट्राइब्स को राजनीतिक आरक्षण दिलाना एवं अन्य।

संपर्क :
आर. के कलसोत्रा
प्रदेश अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर
09419182452

ABOLISH BLASPHEMY LAW & PROTECT DALITS IN PAKISTAN

Vidya Bhushan Rawat

Christian minorities in Pakistan are receiving end as anti-blasphemy law is easily used against them but a close scrutiny of it reveals that basically it is the Sweepers or Bhangi community who are being targeted in Pakistan for their faith. They face regular caste discrimination and untouchability and yet there is no mechanism to protect their interest. Pakistan must enact laws to protect its Dalits.

The notorious blasphemy law in Pakistan has hit again at the 'Christian' minority when a Christian man was charged with blasphemy by a Muslim mob which tried to find him went to Badami Bagh colony of Christians and burnt over 125 houses when could not find the man. It was alleged that there was an altercation between two friends on drinks who happened to be a Muslim and a Christian ultimately resulted in ransacking and dismantling of the property of the tiny Christian minority in Pakistan.

Because of the international repercussion the Pakistan government and the state government of Punjab acted fast, arrested over 130 people and distributed immediate relief to the people yet the fear of the people will not disappear with these dole out as Pakistan need to change its law on Blasphemy which is being used by fanatic Muslims against minorities particularly the Christians and Hindus. Most of the properties belonging to these communities are under the grab by the land mafia in Pakistan who are using such laws for their own benefits. In fact the Lahore incident is also being blamed on the land mafias who wanted to the Christian community to be out from the Badami Bagh area so that they can use the area for commercial purposes.

According to news reports that a mob of over 3000 people by Shafiq Ahmed, looked for the accused Savan, alias Bubby but due to their inability to find him the mob attacked his house, and also burnt the houses of 150 Christian families. Many residents, including women and children, hastily fled to save themselves. The police registered an FIR under section 295-C of the Pakistan Penal Code (death sentence) against Savan and ensuring that he would be given into their custody to decide his fate. They also took Chaman Masih into custody.

World-over there is a growing concern over the misuse of anti-blasphemy law which has put minorities under deep stress and forced them to convert to Islam. Muslim fanatics have used it to grab land of the poor particularly of the Dalits in Pakistan.

Even the UN Human Rights Council is persistently worried about anti blasphemy laws in various countries which result in capital punishment to the accused. In most of the cases these laws are misused. In a report submitted to the Human Rights Council, Heiner Bielefeld said that Countries should repeal all laws punishing blasphemy and people who leave a faith, the United Nations' top expert on freedom of religion said on Wednesday, thrusting himself into a debate between many in the Muslim world and the West. Legislation outlawing apostasy - the act of changing religious affiliation - and insults against religious figures could be used to violate the rights of minorities, said in a report to the UN Human Rights Council. He further said,' "States should repeal any criminal law provisions that penalise apostasy, blasphemy and proselytism, as they may prevent persons belonging to religious or belief minorities from fully enjoying their freedom of religion or belief," he said in the report. Rights campaigners say the blasphemy law in Pakistan is widely used against religious minorities including Christians.'

In Pakistan and many other Islamic countries a non- Muslim can easily be charged with 'hurting' the religious sentiments of Muslims or using abusing language against Prophet Mohammad and Pakistan constitution provide death penalty for such charges. People are arrested on frivolous grounds as a bare FIR would result in arrest of the persons and sending him to the gallows.

It has to be understood that in Pakistan a majority of Christians are actually Dalits in general and predominantly the communities of Sweepers which is contemptuously called as 'Bhangi'. And the Masihs who were attacked were basically sweepers who face untouchability and caste discrimination. They do not get jobs other than sweeping and people do not come near to them. They are completely outcastes and are considered as 'charsis' and 'Bhangedis' which gives the impression that all the people from the sweeper community are drunkard and chain smokers.

In fact 'bhangi' as contemptuous term is the most famous political contempt in Pakistan. Several years back a regional politician called Rehman Malik a 'bhangi' of Benzir Bhutto. A protest of traders yesterday at the Karachi Press Club actually termed the chief minister as 'Bhangi'. India had similar usage of phrase but if any one use such terminology to denigrate a community in public, he or she would face criminal charges but shockingly in Pakistan it is frequently used in daily rhetoric by politicians, activists and even creative people in their songs and soap operas.

Discrimination against the community is rampant and unattended as the interview with Asif Ghani Masih suggests which he gave to a Pakistani newspaper. 'Asif Ghani Masih starts his day by sweeping the dusty corridors of the Sindh Secretariat. As the day progresses, he scrubs dirty toilets and empties dustbins, tasks that are part of his day job as a sanitation worker.

In the evening, however, the 27-year-old becomes a neatly dressed student, who attends classes for a Bachelor's degree; the tasks of the day shelved away as he scribbles notes. At school, he had often dreamt of being an engineer.

"I was hoping that my education would be enough to land me a decent desk job," says Masih, as he sits in his modest house in Old Golimar. "But when the list came out I was shocked to see myself appointed as a sanitary worker in the finance department." His eyes fill with tears as he remembers the day. "It hurts to be called a bhangi [sanitation worker]," he adds.

At the Sindh law department, a Hindu employee, who spoke on condition of anonymity fearing his dismissal from service, said he had completed a college degree but is suffering due to his different beliefs.

"This is what the poor and minorities get for educating themselves," he said. "We are suffering because of our faith." He does not plan to spend money on educating his child, as he believes that won't help him get a decent job in the end. The sanitary worker had got the job on minority quota after he asked for help from his community's political representatives.

"It is sad that uneducated Muslims are appointed as clerks and cannot even write their names, but we are cleaning trash."

The linkage between blasphemy law and the Bhangi community must be understood clearly and so far none has looked into it. Actually, the violence against 'Christian' in Pakistan is actually violence against the Sweeper community who are completely isolated by the mainstream Pakistan society and their issues rarely raised to lime light. Hence whenever the Bhangis have come up in education and asserting themselves, such frivolous charges are raised against them for 'defaming' the 'Prophet' or desecrating Quran. The dirty fact is that Pakistani society is as criminal, racist and caste-ist as their counter parts in India and other parts of South Asia. There is no security protection for them. Their number is miniscule as total minorities in Pakistan remain less than 5% and yet Pakistani society is 'afraid' of them. The Bhangis are considered as dirty, drunkard, untouchable by the Pakistani elite and no constitution protection provided to them. In fact, it is quite shocking that most of the time violence against them is misleading headline meant as violence against Christian. In South Asia caste matters the most and Pakistan is no stranger to this. In fact, the way Pakistani middle classes, writers, singers use term Bhangi to denigrate others puts us to shame. Several years back a Pakistani band produced a super hit sufi song ' Hum Charsi Bhangi hai' which was appreciated very much but it clearly send out a message that Bhangis despite being 'charsi' are the best friends and good at heart. While the messenger wanted to communicate a good message yet it stereotyped a community and strangely enough there was no protest in Pakistan against it. For me it is strange that whenever I listen to this song again and again I do find the usage of Bhangi as contemptuous and full of flaws.

It is time Pakistan government must abolish the draconian blasphemy laws as Pakistan Muslim don't need protection of their identity. Actually, Pakistan needs to pass laws to protect the rights of Dalits and pass the laws. Denigrating God and 'holy book' is offensive and can send you gallows while humiliating and insulting people based on their birth and caste identity can go scot free. Islamic societies in South Asia are rigid, feudal and caste-ist and they need to change their outlook about others. Practice of Untouchability and caste discrimination must be made blasphemous and not the denigration of so-called God that does not exist. It is time to put pressure on each of these countries where caste and untouchability exist to pass laws for the protection of human rights of the Dalits and completely prohibit inhuman practice of untouchability, manual scavenging and caste discrimination.

CENTRE RAPS PRIVATE FIRMS FOR QUOTA FAILURE

Subodh Ghildiyal

NEW DELHI: Amid talk of stimulating growth with sops to industry, the Centre has chided the private sector for performing abysmally on making the workforce inclusive by boosting dalit presence in its ranks.

The industry in 2006 promised voluntary affirmative action to persuade the UPA-1 government to drop plans to enforce reservation in private sector through a legislation.

Reviewing the updated results of affirmative action provided by the industry, Union social justice ministry has shot off letters to Assocham, Ficci and CII, calling the achievements 'minuscule" and "small".

The terse letter from minister Selja says, "I am sure you would agree that these achievements are miniscule compared to the magnitude of the challenge. You would also agree that the progress of affirmative action by your industry chamber needs to be intensified."

In nearly six years of affirmative action policies, CII reported to social ministry this January that 781 of its affiliated companies had adopted the code of conduct, trained 45,000 candidates and provided scholarships to 10,000 students.

Ficci said only 39 companies had adopted its code of conduct while it achieved upgradation/adoption of 110 ITIs and provided training to 11,000 candidates.

Assocham said 783 companies and 172 regional chambers had embraced the code, with training to 10,099 candidates, scholarships to 250 students, coaching to 200 students and entrepreneurship training to 2,600 candidates being provided.

Growing evidence of abysmal delivery on the proposal to boost the presence of SCs and STs in industrial workforce seems to have rattled the ruling Congress whose performance on promise to marginalized sections is coming under greater scrutiny.

There are apprehensions that BSP and activists could pounce on the failure of voluntary action by private sector to accuse Congress of hoodwinking dalits. PM Manmohan Singh accepted the offer of voluntary action just when rising momentum in favour of extending the quota frontier to private sector raised fears among corporates.

The failure to restore "promotion quota" is already being seen as reluctance on Congress's part to pass the constitutional amendment even though it is being blamed on resistance from SP and BJP.

A 'coordination committee' chaired by principal secretary to PM reviews affirmative action and has held six meetings since 2006.

While social justice ministry was unhappy with the industry's performance, its fears were confirmed by a survey by the Indian Institute of Dalit Studies that gave a thumbs down to voluntary action after poring over the results of programmes undertaken by the key chambers. It sought a legally binding law to boost affirmative action.

The survey, submitted to minister Selja, concluded, "The voluntary and self-regulatory nature of the policy has not worked. There is, thus, a need for more government regulations and directives with definite and mandatory provisions."

According to the survey, out of 90,000 direct and indirect member companies of CII, only 794 had signed up. Of 4 lakh member companies/professionals aligned with Assocham, only 100 companies had agreed, with its central office implementing 50 programmes to promote education and skills. Ficci's indirect membership of over 2.50 lakh companies stayed away from affirmative action with "only one initiative in Sonbhadra (UP)".

Also, less than one-third of affirmative action projects were exclusively for SC/STs and the bulk were diffused over a larger section like the poor and underprivileged.

(Courtesy : The Times Of India)

Caste Based Discrimination in U.K. Demonstrations & Debate Outcome in the House of Lords

Rosemary

There are about 4,80,000 Dalits in U.K. who are concerned about discrimination against them in the country. Recently demonstrations on this issue were held outside the Parliament. The House of Lords took note of this issue on 8.3.2013. The previous Government which was aware of this situation introduced an order-making power into the Equality Act 2010 and to assess the evidence commissioned a report from the National Institute for Economic and Social Research. The NIESR concluded that there is clear evidence of discrimination in the areas covered by the Equality Act, 2010, namely, education, employment and the provision of public goods and services and it recommended legislation by inserting "(d) caste" . The study confirmed that discrimination and harassment on caste lines existed in n U.K. Members of the view that nothing could be more significant and effective in reducing discrimination on the grounds of caste than to have clear-cut law saying that discrimination in the public sphere will not be tolerated. At the moment, when a person believes that he has been discriminated against because of his caste, he has no legal means of redress.

Some Members expressed a surprise and a shock to learn that caste prejudice has come to this country which, of course, is not in that extreme form but it needs to be shown that it is totally unacceptable which can clearly be done by this amendment.

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:

Five years : Rs. 600/-

One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 8 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 March, 2013

मादक पदार्थों से दूर रहें।

-गौतम बुद्ध

CASTE CONSCIOUSNESS OF COMMUNISTS

Dr. Udit Raj

Ashish Nandi's speech at the Jaipur Literary Festival is not completely untrue, rather one portion is laced with hard facts. He called Dalits and Backwards as corrupt and now the Scheduled Tribe people are also becoming corrupt. He also said that corruption in West Bengal is relatively less but at the same time, in the last one hundred years, no Dalit or Backward leadership has emerged. It has very deep-rooted implications as to why in the strong-hold of Communists, no Dalit or Backward leadership has emerged whereas West Bengal should have produced maximum number of such leaders. The entire Dalit-Adivasi society is largely proletariat. The definition of "proletariat" as given by Karl Marx fits in more appropriately with Dalits and Adivasis than anywhere else because they have not only been exploited economically but mentally also. If on the one hand, Communists do not believe in casteism, then why the reins of power are in the hands of upper caste in West Bengal. According to the Karl Marx ideology, the political power should first of all be in the hands of Dalits, secondly with the Tribals and then with Backwards but this did not happen.

Karl Marx gave maximum emphasis on economic exploitation. According to him, a big portion of the labour put in by a worker in production, goes to the booty of the capitalist, which Karl Marx termed as surplus value. The integrity and farsightedness with which he understood the European and Russian societies has not been shown by anyone in the Indian society except a few people in the twentieth century and the most prominent among them was Dr. Ambedkar. The intellectual class in our country has been unsuccessful in bringing about social change in the society and has not been able to rise above the caste-mould. It is unfortunate that there is hardly any intellectual in the country who will admit this bitter truth that in their thinking and writings, they are above caste feelings. It is surprising that in our country, people say something and do something else. There may be hardly any person in the country who does not speak against caste system but there are hardly any persons who sincerely want to break the shackles of the caste system.

The social exploitation of Dalits in the Indian society is much more severe than economic exploitation of the proletariat in Europe and America but have the Communists taken note of this factor? The capitalists in those countries have at least been honest to the extent that they adopted the concerned sections of the society and and jointly harvested the benefits but in the caste-ridden Indian society, nothing like that has happened. It is because of the efforts of the rich people in Europe and America that the benefits of Education and Science percolated to the proletariat. The rich did not only invest in inventing new technology, plant and machinery and tools but also took active part in these activities. Even now they are investing more in research and Science even though situation has changed considerably in the present context when the need to do so is not so acute. This year America invested 366 billion dollars on research and development which is more than the investment made by any country in the world in this area. This plainly means that if the capitalists of these countries exploited the workers, in return, they gave them something also. The capitalists have made significant contributions in many areas including literature. Maybe the capitalists might have done so to increase their profits or just to produce consumer items for comfort and luxury.Are the Indian communists aware of this stark reality? Had they really taken note of this situation arising from the exploitation of Dalits and Backwards in the Indian society, they would have taken up the cudgels for the casue of Dalits and Backwards.

The upper caste people have not made any significant contribution to increase productivity either as per religious scripture or in actual practice. The so-called upper caste people considered any type of manual work below their dignity which situation prevails till date. Despite being owners of hundreds of thousands of acres of land, they hardly tilled land themselves or used an axe to do some manual work because they considered it as below their dignity. Thus the capitalists of the Indian society are much bigger parasites than their counterparts in Europe and America. Of course, the upper caste people in the Indian society, controlled all the resources of production but did not make any investment in research and development with the result that wealth could be built up only up to a limited extent. Not very long ago, in my childhood, I found that when landlords incurred heavy losses, avoided doing any labour to set things right because this was below their dignity. Even when a canal was o\ver-flooded which was causing damage to the crops, they would not make any efforts to stop this because it affected their prestige. Even when there is a famine like situation in the fields and there is plenty of water in the canal, they would continue to wait for the farm hands so that they may come and irrigate the fields. This example reflects the mindset of the uppercaste people. If such things happened in the 20th century, then it is not difficult to perceive as to what might have happened in the previous centuries.

Dalits and Backwards have not only suffered economic exploitation but have also been victims of mental exploitation.If there was exploitation of labour in Europe, in the Indian society, both labour and dignity respect were exploited.Indian Communits have not paid any heed to the exploitation of self-respect of Dalits and Backwards. All the time they were harping that with the development of education and urbanization, caste system will automatically disappear. The

Indian communists succeeded to some extent in convincing the SC/ST in West Bengal about their stand on this issue due to which they could expand their hold there. They were expanding their hold in Uttar Pradesh and Bihar but suffered a great set-back when winds of change swept severely in national and international fields on the issue of communism. In the year 1990, when USSR dis-integrated, it had widespread adverse impact on Communists all over the world. With the passage of time and because of the spread of Information and knowledge, in the decade of 1970-1980, Dalits awakened and started asking for a share in governance and that led caste polarization in politics.The mental exploitation of Dalits and Backwards was much more than the economic exploitation which is still prevalent. Leaders of Dalits and Backwards took note of this situation and people from different castes rallied behind them. Had the Indian Communits realized this social and religious reality, leadership among Dalits and Backwafrds on caste lines would not have appeared on the surface but on the basis of thje proletariat class.

When the Indian communists have not realized this social and religious reality, they could not muster the courage to encourage leadership of Dalits and Backwards. If the leadership of Dalits and Backwards is not able to emerge on these lines not only in West Bengal but in other States also, it is so only because of this well-planned conspiracy or ignorance. In this conext, Ashish Nandy's statement is not ony correct but relevant only. Had a person of the caliber of Karl Marx been born in India, he would have shaped himself very much like Dr. B.R. Ambedkar. The caste exploitation in the country is so acute that mentally Dalits and Backwards have been rendered dis-abled and made to believe in fate. No whipping was required to suppress them but this was termed as a divine commandment. Karl Marx termed religion as opium in the Western context. What would the Indian communists call religion in the Indian context? Had the Indian Communists realized that the mental exploitation of Dalits and Backwards is much more dangerous and poisonous than opium and projected it accordingly, Marxism would have come to India soon after it established its hold in Russia. Indian soil was much more fertile for communism than Europe but the upper caste communists did not realize this reality. On the one hand, they launched a struggle for the economic emancipation of the toiling masses but on the other hand , they did not pay any attention to the social and mental exploitation of Dalits and Backwards for which they are paying a heavy price.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn